

ÒEGISTERPIV_/No. D-(D)-72

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 11-खण्ड 3-उपखण्ड (1)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]

नई दिल्लो, सोमवार, मई f 16, f 1977/बैशाख f 26, f 1899

No. 163]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 1977 VAISAKHA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृथ्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May 1977

G.S.R. 241 (E).—The following Proclamation by the President is published for general information —

Whereas, I, Basappa Danappa Jatti, Vice-President acting as President of India, have received a report from the Governor of the State of Manipur and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution"),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I-

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely —
 - (i) In the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the sald State,
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely
 - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
 - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the Reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India,

articles 163 and 164,

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State,

articles 167 and 169,

clause (1) of article 174; articles 175, 176 and 177,

clause (c) of article 179 and the first proviso thereto;

articles 181, 188, 189, 193, 194, 196 and 198,

clauses (3) and (4) of article 199, articles 208 to 211 (both inclusive),

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213, and so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State,

- (iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parhament, and, in particular, references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively.
- Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State,
- (iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law, as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi¹ The 16th May, 1977 B, D, JATTI,

Vice-President acting as President

[No, V/11013/7/77-S&P(DV)]

M L KAMPANI, Jt Secy.

New Delhi; The 16th May, 1977.

ORDER

New Delhi, the 16th May 1977

G.S.R.~242 (E).—The following Order by the President is published for general information—

In pursuance of sub-clause (1) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 16th day of May, 1977, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Manipur and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State

B D JATTI,

Vice-President acting as President

New Delhi, The 16th May, 1977

[No V/11013/7/77-S&P (DV)]
M L. KAMPANI, Jt Secy.

New Delhi, The 16th May, 1977

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1977

सा॰ का॰ नि॰ 241(भ्र).—राष्ट्रपित द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही हैं ---

यत. मुझे, भारत के राष्ट्रपित के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपित बसप्पा दानप्पा जत्ती को मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, भौर इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमे राज्य का शासन भारत के सविधान (जिसे इसमे इसके पश्चात् "सविधान" कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

भ्रतः भ्रव मै, सविधान के श्रनुच्छेष 356 द्वारा प्रदत्त गक्तियो का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली भ्रन्य सभी गक्तियो का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उद्घोषणा करता हं कि मै—

- (क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य धीर इस राज्य के राज्यपाल मे निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तब्य सभी गक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वय सम्भालता हु;
- (ख) घोषित करता हू कि उक्त राज्य के विधान मङल को शक्तिया संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के प्रधीन प्रयोक्तव्य होगी ; श्रौर

- (ग) निम्नलिखित श्रानुपर्गिक श्रौर पारिषामिक उपबध करता हू जो इस उद्-घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे ग्रावश्यक या वाछनीय प्रतीत होते हैं ; अर्थात् .--
 - (i) उस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए क्रत्यों श्रीर शक्तियो का प्रयोग करने मे, मेरे लिए भारत के राष्ट्र-पित के रूप मे उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझ् उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;
 - (ii) उक्त राज्य के सबध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एनदृद्वारा निलबित किया जाता है, श्रर्थात् —

भ्रनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सबध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है ,

श्रनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत का नियल्लक श्रौर महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मडल के समक्ष रखे जाने से है;

ग्रनुष्छेद 163 **भौ**र 164 ;

श्रनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्य के मित्रयों के बीच बटवारे से हैं ;

भ्रनुच्छेद 167 भौर 169 ;

भ्रानुच्छेद 174 का खण्ड (1) ब्रानुच्छेद 175, 176, श्रौर 177 ;

ग्रनुच्छेद 179 का खण्ड (ग) श्रीर उस **धनुच्छेद का प्र**थम परन्तुक ;

भन्**न्छेद 181, 188, 189, 193, 194, 196 भौर** 198 ;

धनुच्छेद 199 का खण्ड (3) और खण्ड (4) ;

ग्रनुच्छेद 208 से 211 (जिसमें ये दोनों सम्मिलित है) ;

श्रनुच्छेद 213 वेः खण्ड (1) का परन्तुक श्रीर खण्ड (3) का परन्तुक;

ग्रनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध ज्ञापन सहित रिपोर्ट की राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) सिवधाम में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का ग्रर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा ग्रीर उसमे राज्य के विधान मडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों ग्रीर उसकी मिक्तयों से हैं, ग्रर्थात, जब तक कि संवर्भ द्वारा श्रन्यथा ग्रेपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा भौर विशिष्टतया श्रनुच्छेद 213 में राज्यपाल ग्रीर राज्य के विधान मण्डल या उसके सवनों के प्रति निदेशों का ग्रर्थ, क्रमण. राष्ट्रपति ग्रीर ससद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ;

परन्त इसमे की कोई बात अनुक्छेद 153, अनुक्छेद 155 से लेकर अनुक्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुक्छेद 299 और अनुक्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खण्ड के उपखण्ड (i) े अधीन उस सीमा तक जहा तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने में निवारित करेगी:

(iv) सविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्द्वारा बनाए गए श्रिधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे श्रर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के श्राधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, और साधारण खण्ड श्रिधिनियम 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लाग है, ऐसे किसी श्रिधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मण्डल का श्रिधिनियम हो।

नई दिल्ली ; 16 मई, 1977 बसप्पा दानप्पा जल्ती, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए जप-राष्ट्रपति ।

[स॰ V/11013/7/77-एस एण्ड पी (डी-V)]

नई दिल्ली ; 16 मई, 1977

मनोहर लाल कम्पानी, सयुक्त सचिव।

श्रादेश

नई दिल्ली, 16 मई, 1977

सा॰ का॰ नि॰ 242(प्र).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित प्रादेश सर्वसाधारण के सुचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है.—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज मई, 1977 के सोलवें दिन जारी की गई उर्भोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि मिणपुर राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के भिष्ठीन उस राज्य के राज्याल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियो, जिनको राष्ट्रपति ने

उक्त उद्भोषणा के खण्ड (क) के श्राधार पर स्वयं सम्भाल लिया है, राष्ट्रपति के श्रधीक्षण, निर्देशन भौर नियंत्रण के श्रध्याधीन रहते दुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगा।

नई विल्ली ; 16 सई, 1977 बसप्पा वानप्पा जत्ती, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

[सं॰ V/11013/7/77-एस एंड पी (डी-V)]

सर्व विक्ती ; 16 मर्च, 1977

मनोहर लाल कम्पानी, संयुक्त सचिव।